

'ग्रीन वॉयस' पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सचिवाई वभाग के पूर्व अधीक्षण अभियंता शवि सहि रावत को क्षेत्र में [सतत पर्यावरणीय प्रथाओं](#) को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिये, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, एक [गैर-सरकारी संगठन \(NGO\)](#) द्वारा 'ग्रीन वॉयस' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बडि

- यह पुरस्कार नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के स्थापना दविस पर प्रदान किया गया, जो पूरे भारत में [जल संरक्षण](#) पर सक्रिय रूप से काम करने वाला संगठन है।
 - शवि सहि रावत ने सामाजिक कार्यों में अपने वर्षों के योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें नमिनलखिति महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
 - जल संरक्षण एवं [पर्यावरण संरक्षण](#)।
 - फल रोपण अभियान।
 - शक्तिषा और स्वास्थ्य सुवधियों में वृद्धि करना।
- [महिला सशक्तीकरण](#) को बढ़ावा देना।
- [क्षेत्रीय योगदान](#):
 - उनका कार्य पलवल, गुडगाँव, मेवात और फरीदाबाद सहित कई क्षेत्रों में वसितुत है।
- उन्होंने क्षेत्र में [जल संरक्षण](#) के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये ['यमुना बचाओ अभियान'](#) के समन्वयक के रूप में भी काम किया।

//

भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- Ⓢ समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
 - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
 - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- Ⓢ नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- Ⓢ भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- Ⓢ **सफलता की कहानियाँ:**
 - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
 - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- Ⓢ जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
 - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- Ⓢ **विनियमन अधिनियम:**
 - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
 - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- Ⓢ **97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
 - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
 - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- Ⓢ **उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- Ⓢ पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- Ⓢ **पंजीकृत:**
 - **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
 - **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
 - **कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- Ⓢ **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 19(1)(c)**- संघ बनाने का अधिकार
 - **अनुच्छेद 43**- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
 - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

प्रमुख NGO:

- **NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
- **अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।



Drishti IAS